

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, वाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

राजस्व प्रकरण सं. 21/2016 GCMS NO2016/00056

दायरा तिथि : 03.03.2016

निर्णय तिथि : 21-3-2016

वादी:-

राजस्थान सरकार जारिये (भूमिधारी)

तहसीलदार, वाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. विक्रमादित्यसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह
2. गंगारिंह पुत्र खेतसिंह
3. भैरूरिंह पुत्र खीगसिंह
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र नरपतरिंह
5. लादुरिंह पुत्र दुर्जनसिंह जातिगण राजपुत
निवासीगण फालना स्टेशन तहसील वाली
6. गदनलाल पुत्र जीवराज जाति कलाल
निवासी फालना स्टेशन तहसील वाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति :-

1. नायब तहसीलदार, वाली परोकार सरकार की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 की ओर से

:-: निर्णय :-:

दिनांक : 21-3-2016

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, वाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड व गौका की स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम रोला तहसील वाली में स्थित भूमि खरारा नंबर 81 रकबा 1.70 हेक्टर का कृषि भिन्न यानि अकृषि प्रयोजनार्थ यथा आवारीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ में उपयोग में लिया जाना पाये जाने से प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अपने प्रार्थना में प्रार्थी तहसीलदार, वाली द्वारा वर्णित किया गया कि गौके पर बिना संपरिवर्तन करवाये आवारीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ 200x 60=12000 वर्गफीट में आटा पिराने की फैक्ट्री लगाई हुई है, तथा पुरे खरारे में प्लॉटिंग कर आवारीय प्रयोजन उपयोग में लिये जाने की चेष्टा की जा रही है, अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण पंजिवद्ध कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा तथा अप्रार्थी संख्या-06 के अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह द्वारा प्रकरण को कन्टेस्ट किया गया। प्रकरण को कन्टेस्ट करने से आगे की कार्यवाही वाद के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण के चलते दिनांक 04.11.2016 को अप्रार्थी संख्या-06 गदनलाल व उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-06 के द्वारा रोला के खरारा नंबर 81 रकबा 1.70 हेक्टर में से खरीद शुदा 1 बीघा (0.16 हेक्टर) का आवारीय कॉलोनी से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या-06 को उद्योग विभाग द्वारा उक्त भूमि पर दलीया व्यवसाय का उद्योग लगाने वास्तु अनुमति पत्र जारी किया हुआ है, जिससे अप्रार्थी संख्या-06 की खरीद शुदा एक बीघा भूमि को डिवाइड रखते हुये कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र वकूलाय को सुनने के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 04.11.2016 से प्रतिवादी संख्या-06 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप करते हुये पत्रावली को प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के जवाब के रखा गया। दिनांक 19.12.2016 का प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या-06 की एक बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की भूमि गौके पर अलग-अलग बंटी हुई है, लेकिन रेकर्ड में भूमि शामलाती में दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया जा रहा है। भूमि का बंटवाडा करने के उद्देश्य से पीलर खड़े किये है लेकिन अकृषि प्रयोजनार्थ आज दिन तक कोई नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रकरण में धारा 177 RTA. का उल्लंघन नहीं होने से कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया। वादे व जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में वाद विन्दु कायमी के पश्चात् वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखी गई।

पेज लगातार.....02

दिनांक 21.01.2019 को वादी पेशेकार सरकार ने प्रकरण प्रस्तुती के समय प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अतिरिक्त नया कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिससे दिनांक 21.01.2019 की आदेशिका से वादी पक्ष की मौखिक साक्ष्य का अवसर बंद करते हुये प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये पत्रावली को रखा गया। प्रकरण के चलते न्यायालय द्वारा वर्तमान गौका रिपोर्ट भी तलब की गई। दिनांक 20.07.2021 को वर्णित भूमि का निरीक्षक भू0अ0 खुडाला व पटवारी हल्का, धणी द्वारा गौका निरीक्षण के पश्चात् गौका फर्द प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी पक्ष को भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 30.07.2021 को प्रतिवादी पक्ष के साक्ष्य का अवसर भी बंद करते हुये प्रकरण को बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकूलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय बहस के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद विन्दुओं को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

1. आया प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 द्वारा ग्राम सेला तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है ?.....वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी तहसीलदार, बाली का था। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात है कि पटवारी हल्का, धणी व निरीक्षक भू0अभिलेख खुडाला की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2016 को इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण प्रस्तुत हुआ है, इस बाबत दिनांक 23.02.2016 को पटवारी हल्का, खुडाला द्वारा जो गौका फर्द तैयार की गई है, उस गौका फर्द के अनुसार गौके पर खसरा नंबर 81 कुल रकबा 1.70 हैक्टर किरम बाराणी सोयम में कृषि भूखण्ड कटे हुये हैं, व इसी खसरा नंबर में गदनलाल पुत्र जीवराज जाति मेवाडा कलाल की लम्बाई में 200 फीट एवं चौड़ाई में 60 फीट की आटा पिसाने की फैक्ट्री लगी हुई है जो चालु है। तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ में भू0 आवंटन नहीं है, उक्त खसरा नंबर पर इस फैक्ट्री के अलावा अन्य गकान या किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है। पूरे खसरे में भूखण्ड कटे हुये हैं और भूखण्ड के निशान सीमेन्ट के पिलर लगाकर किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरण प्रस्तुती के समय उक्त गौका फर्द के अनुसार गौके पर खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर में $200 \times 60 = 12000$ वर्गफीट में आटा पिसाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। इसके अलावा शेष भूमि पर किसी प्रकार का आवारीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना प्रस्तुत गौका फर्द दिनांक 23.02.2016 से प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा जवाबदावा में यह उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि सह खातेदारी की भूमि है, जो रिकार्ड में शागलाती दर्ज है, परन्तु गौके पर प्रत्येक खातेदार के हिस्सा अनुसार बंटवारा किया है, तथा अलग-अलग हिस्सों के निशान पीलर लगाकर किये हुये हैं। भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के प्रमाण स्वरूप गौके के फोटो चित्र भी पेश किये गये हैं, जिन फोटो चित्रों के अवलोकन से भी यह प्रमाणित है कि भूमि गौके पर पडत पड़ी है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने जवाब में उल्लेखित किया कि वाद में उल्लेखित भूमि ग्राम सेला के खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या-06 गदनलाल की भूमि एक बीघा में $200 \times 60 = 12000$ वर्गफीट में आटा पिसाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। दिनांक 04.11.2016 को प्रतिवादी संख्या-06 के एक बीघा (0.16 हैक्टर) भूमि के संबंध में कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। इस प्रकार जिस भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा था, उसके विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2016 को ड्रॉप की जा चुकी है। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा वर्तमान में तलब गौका स्थिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निरीक्षक भू0अ0 खुडाला व पटवारी हल्का, खुडाला द्वारा दिनांक 20.07.2021 को जो गौका फर्द तैयार की गई है। इसके अवलोकन से भी वर्णित भूमि पर पत्थर की छीणों से तारबंदी कर प्लॉट किया होना बताया, परन्तु गौके पर किसी प्रकार का निर्माण अथवा आवारीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। प्रकरण प्रस्तुती के समय की गौका फर्द एवं वर्तमान गौका फर्द में वर्णित तथ्यों के अनुसार केवल मात्र गौके पर छीणा क टुकड़े लगाकर तारबंदी करना ही प्रकट होता है, किसी रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि गौके पर आवारीय प्रयोजन उपयोग हो रहा है अथवा निर्माण कार्य हुआ हो। जिससे वकील प्रतिवादीगण की दलीलों को मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि प्रकरण में वर्णित भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है। जब वर्णित भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग में ही नहीं हो रहा है तो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का प्रकरण में किसी प्रकार से उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं है। जिससे तनकी संख्या 01 वादी के विरुद्ध व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया प्रतिवादीगण बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भिन्न उपयोग में लेने हेतु विधि अनुसार बाधित है ?.....

// 03 //

राजस्व प्रकरण सं. 21/2016 GCMS NO2016/00056
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम विक्रमादित्यसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादी तहसीलदार, बाली का था। तनकी संख्या-01 में किये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम सोला के खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हेक्टर में प्रतिवादी संख्या-06 मदनलाल पुत्र खीमराज के हिस्सा की भूमि एक वीघा मेंसे 200x 60=12000 वर्गफीट में आटा पिसने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। जिसके संबंध में न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.11.2016 को प्रतिवादी संख्या-06 के एक वीघा (0.16 हेक्टर) भूमि के संबंध में कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। इस प्रकार जिस भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा था, उसके विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2016 को ड्रॉप की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के हिस्सों की भूमि पर किसी प्रकार की अकृषि प्रयोजनार्थ गतिविधि तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार प्रमाणित नहीं है। जब वर्णित भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिया जाना साबित ही नहीं है तो कृषि भिन्न उपयोग में लेने हेतु विधि अनुसार बाधित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जिससे तनकी संख्या-02 प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पक्ष में तथा वादी तहसीलदार, बाली के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का कृषि भिन्न उपयोग नहीं किया है। सह खातेदारों के बंट हिस्से अनुसार मौके पर निशानात किये थे। जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं है प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या-01 से 05 का था। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के द्वारा जबाबदावा में उल्लेखित तथ्यों से यह प्रमाणित है कि सह खातेदारों के बंट हिस्से अनुसार मौके पर निशानात किये थे। जिसकी पुष्टि जबाबदावा के साथ प्रस्तुत मौके के फोटो चित्र एवं प्रकरण प्रस्तुती के समय पटवारी हल्का, धणी द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 23.02.2016 एवं वर्तमान में दिनांक 20.07.2021 को तैयार मौका फर्द व मौके के फोटो चित्रों से भी यह बखूबी प्रमाणित है कि वर्णित भूमि पर किसी प्रकार की अकृषि प्रयोजन गतिविधि नहीं हो रही है, भूमि मौके पर पडत पडी है। जिससे उक्त तनकी भी प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पक्ष में तथा वादी तहसीलदार, बाली के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 01 से 03 वादी के विरुद्ध निर्णित होने एवं ग्राम सोला के खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हेक्टर मेंसे प्रतिवादी संख्या-06 मदनलाल की एक वीघा भूमि के संबंध में न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.11.2016 से कार्यवाही ड्रॉप होने तथा शेष रही भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना साबित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की भूमि के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। इसी कदर डिक्री पूर्वा जारी हो। पत्रावली फेराल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री प्रदीप प्रकाश)
आई.एस.

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 21-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली